



हिमाचल प्रदेश

राजपत्र

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 24 जनवरी, 2007/4 माघ, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24 जनवरी, 2007

संख्या एल० एल० आर०-डी(6)-38/2006-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-01-2007 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख-सुविधाएं) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 32) को वर्ष 2007 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

जे० एन० बारोवालीया,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख-सुविधाएं) अधिनियम, 2006

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. परिभाषाएं।
3. नियुक्ति।
4. शक्तियां और कृत्य।
5. विशेषाधिकार और सुख-सुविधाएं।
6. पद की और गोपनीयता की शपथ।
7. वेतन और भत्ते।
8. निवास स्थान।
9. वाहन भत्ता।
10. संसदीय सचिव द्वारा सदस्य के रूप में वेतन या भत्तों का न लेना।
11. संसदीय सचिव द्वारा वृत्ति आदि न करना।
12. नियम बनाने की शक्ति।

2007 का अधिनियम संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख-सुविधाएं) अधिनियम, 2006

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 23 जनवरी, 2007 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियों, विशेषाधिकारों और सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव संक्षिप्त (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख-सुविधाएं) अधिनियम, नाम। 2006 है।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न परिभाषाएं हो,—

(क) "मुख्य मन्त्री" से हिमाचल प्रदेश का मुख्य मन्त्री अभिप्रेत है;

(ख) "सदस्य" से हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य अभिप्रेत है;

(ग) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(घ) "संसदीय सचिव" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन संसदीय सचिव या मुख्य संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा का सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(च) "विनिर्दिष्ट" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है।

नियुक्ति।

3. मुख्य मन्त्री, संसदीय सचिवों को ऐसी संख्या में नियुक्त कर सकेगा और उनमें से प्रत्येक को ऐसे कर्त्तव्य और कृत्य सौंप सकेगा, जैसे वह उचित समझे ।

शक्तियां और
कृत्य।

4. (1) संसदीय सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) संसदीय सचिव को, प्रभारी मन्त्री के विचार हेतु नस्ति पर प्रस्ताव के प्ररूप में अपना टिप्पण अभिलिखित करने के सिवाय, सचिव या सरकार के किसी अन्य अधीनस्थ कृत्यकारी द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई को अनुमोदित करने की शक्तियां नहीं होंगी ।

विशेषाधिकार
और
सुख—
सुविधाएं।

5. संसदीय सचिव ऐसे विशेषाधिकारों और ऐसी सुख— सुविधाओं का हकदार होगा, जैसी सदस्यों को उपलब्ध हैं ।

पद की और
गोपनीयता
की शपथ।

6. किसी संसदीय सचिव द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्य मन्त्री उसे निम्नलिखित रीति में पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा:—

“मैं, , ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा ।”

वेतन और
भत्ते।

7. मुख्य संसदीय सचिव प्रति मास ग्यारह हजार रुपए वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा जबकि संसदीय सचिव प्रतिमास दस हजार रुपए वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, संसदीय सचिव ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी सदस्यों को अनुज्ञेय हैं।

8. (1) प्रत्येक संसदीय सचिव को, एक सुसज्जित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या ऐसे गृह के स्थान पर, निम्नलिखित दरों पर भत्ता संदत्त किया जाएगा; अर्थात्:—

(क) मुख्य संसदीय सचिव तीन हजार रुपए प्रति मास;
और

(ख) संसदीय सचिव दो हजार पांच सौ रुपए प्रति
मास।

(2) राज्य सरकार संसदीय सचिव को दिए गए गृह को उसे, संसदीय सचिव न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए, अधिभोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

(3) प्रत्येक संसदीय सचिव, उसे आबंटित सुसज्जित गृह के बारे में, उसके वेतन के दस प्रतिशत की दर से लाइसेंस फीस संदत्त करने का दायी होगा और वह उसके वेतन से प्रति मास वसूलीय होगी।

स्पष्टीकरण.—संसदीय सचिव ऐसे किसी मामले में जहां उसको आवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

9. प्रत्येक संसदीय सचिव एक कार का, जिसके अनुरक्षण और वाहन नोदन का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी या उसके स्थान पर तीन सौ रुपए प्रतिमास की दर से वाहन भत्ते का, हकदार होगा।

10. इस अधिनियम के अधीन वेतन या भत्ते प्राप्त करने वाला कोई भी संसदीय सचिव सदस्य के रूप में वेतन या भत्तों के तौर पर कोई भी राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

सचिव द्वारा
सदस्य के
रूप में वेतन
या भत्तों का
न लेना।

संसदीय सचिव द्वारा कोई वृत्ति आदि न करना। 11. कोई भी संसदीय सचिव अपने इस पद के दौरान, ऐसे संसदीय सचिव के कर्तव्यों से अन्यथा, कोई भी वृत्ति नहीं करेगा या किसी व्यापार या वाणिज्य में नहीं लगेगा या पारिश्रमिक के लिए कोई भी नियोजन अपने हाथ में नहीं लेगा।

नियम बनाने की शक्ति। 12. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES
(APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS,
PRIVILEGES AND AMENITIES) ACT, 2006**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.
2. Definitions.
3. Appointment.
4. Powers and functions.
5. Privileges and amenities.
6. Oath of office and secrecy.
7. Salaries and allowances.
8. Residence.
9. Conveyance allowance.
10. Parliamentary Secretary not to draw salary or allowances as member.
11. Parliamentary Secretary not to practise profession etc.
12. Power to make rules.

**THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY
SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES,
ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND
AMENITIES) ACT, 2006**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 23rd JANUARY, 2007)

AN

ACT

*to provide for the Appointment, Salaries, Allowances, Powers,
Privileges and Amenities etc. of the Parliamentary Secretaries in the
State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Chief Minister” means the Chief Minister of Himachal Pradesh;
- (b) “member” means a member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh;
- (c) “notification” means a notification published under proper authority in the Official Gazette;
- (d) “Parliamentary Secretary” means a member of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh appointed as the Parliamentary Secretary or the Chief Parliamentary Secretary under section 3 of this Act;
- (e) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act; and
- (f) “specified” means specified by notification published in the Official Gazette.

3. The Chief Minister may appoint such number of the Parliamentary Secretaries, and assign to each of them such duties and functions, as he may deem fit. Appoint-ment.

4. (1) A Parliamentary Secretary shall exercise such powers, discharge such functions and perform such duties as may be specified by the Chief Minister. Powers and functions.

(2) A Parliamentary Secretary shall not have the powers to approve the action proposed by a Secretary or any other subordinate functionary of the Government, except recording his note in the form of proposal on the file for the consideration of the Minister-In-Charge.

5. A Parliamentary Secretary shall be entitled to such privileges and amenities as available to the members. Privileges and amenities.

6. Before a Parliamentary Secretary enters upon his office, the Chief Minister shall administer to him oath of office and secrecy in the following manner:— Oath of office and secrecy.

“I, _____, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Parliamentary Secretary for the State except as may be required for the due discharge of my duties as such Parliamentary Secretary.”

7. A Chief Parliamentary Secretary shall be entitled to the salary of Rs. 11,000/- per month, while a Parliamentary Secretary shall be entitled to a salary of Rs. 10,000/- per month. In addition, the Parliamentary Secretary shall be entitled to compensatory allowance and other perquisites as are admissible to the members. Salaries and allowances.

8. (1) A Parliamentary Secretary shall be provided with a furnished house, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu of such house, shall be paid an allowance at the following rates, namely:— Residence.

(a) a Chief Parliamentary Secretary Rupees three thousand per mensem; and

(b) a Parliamentary Secretary Rupees two thousand and five hundred per mensem.

(2) The State Government may allow a Parliamentary Secretary to continue in occupation of the house provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be a Parliamentary Secretary.

(3) A Parliamentary Secretary shall be liable to pay licence fee at the rate of 10% of his salary in respect of the furnished house allotted to him and the same shall be recoverable monthly from his salary.

Explanation.— A Parliamentary Secretary shall not become personally liable for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds the amount specified in sub-section (1).

Conveyance
allowance.

9. A Parliamentary Secretary shall be entitled to the use of a car, the expenses on the maintenance and propulsion of which shall be borne by the State Government or in lieu thereof to a conveyance allowance at the rate of rupees three hundred per mensem.

Parliamentary
Secretary
not to draw
salary or
allowances
as member.

10. No Parliamentary Secretary, in receipt of a salary or allowances under this Act, shall be entitled to receive any sum by way of salary or allowances as member.

Parliamentary
Secretary not
to practise
profession
etc.

11. A Parliamentary Secretary shall not, during his office as such, practise any profession or engage in any trade or commerce or undertake for remuneration any employment other than his duties as such Parliamentary Secretary.

Power to
make the
rules.

12. (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.